लोक टुडे
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

PK टाइम्स

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 304 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | मंगलवार, 19 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

अब विदेशी कपड़ों की जगह 'मेड इन थार' जैकेट पहनेंगे भारतीय जवान

थार का 'आक' माइनस 40 डिग्री में रखेगा जवानों को गर्म

रूमा देवी फाउंडेशन और उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजस्थान के थार रेगिस्तान में उगने वाला आक का पौधा, जिसे कभी बेकार खरपतवार समझकर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब माइनस टेम्प्रेचर में देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों के लिए सुरक्षा कवच बनने जा रहा है। इस प्राकृतिक और हल्के फाइबर से बने कपड़े -20°C से -40°C तक के बर्फीले तापमान में भी शरीर को पूरी तरह गर्म रखने में सक्षम हैं। रूमा देवी फाउंडेशन ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के साथ हाथ मिलाया है। लैब टेस्टिंग में यह साबित हुआ कि आक के डोडों से निकलने वाले खोखले रेशे हवा को अपने अंदर रोककर रखते हैं। यह तकनीक -20°C से -40°C के जानलेवा तापमान में भी शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सेना के जवान अभी जो भारी कपड़े पहनते हैं, उनके मुकाबले आक फाइबर से बने जैकेट और स्लीपिंग बैग का वजन बेहद कम होता है। यह रेशा प्राकृतिक रूप से नमी को सोखता नहीं है, जिससे यह बर्फबारी वाले इलाकों के लिए सबसे बेस्ट है। वर्तमान में भारतीय सेना सियाचिन और लद्दाख जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए विशेष थर्मल कपड़े अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों से आयात करती है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। रूमा देवी की इस पहल और स्वदेशी तकनीक से अब भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।

अब रेगिस्तान में होगा कलेक्शन पॉइंट

इस नई कपड़ा क्रांति के लिए रूमा देवी फाउंडेशन ने बाड़मेर में एक विशेष कलेक्शन पॉइंट बनाया है। स्थानीय ग्रामीण और महिलाएं खेतों व बंजर भूमि से आक के फलों (आक-पाडिया) को तोड़कर इन केंद्रों पर लाएंगे। फाउंडेशन द्वारा ग्रामीणों से 20 रुपये प्रति किलो की दर से इन डोडों की खरीद की जाएगी। जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। एकत्रित किए गए डोडों को जालीदार कट्टों में भरकर गाजियाबाद (यूपी) और मुंबई (महाराष्ट्र) के अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांटों में भेजा जाएगा, जहां मशीनों के जरिए रेशों को अलग कर कपड़ा तैयार होगा।

पर्यावरण और किसानों को दोहरा लाभ :

आक एक मरुस्थलीय पौधा है जिसे न तो पानी की जरूरत होती है और न ही किसी खाद-उर्वरक की। यह बंजर जमीन पर भी आसानी से उग जाता है।एक बार लगाने के बाद यह पौधा 10 से 12 वर्षों तक लगातार फल देता रहता है, जिससे किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के साल के 3 महीनों के सीजन में बंपर कमाई का जरिया मिल गया है।

जवानों को कड़ाके की ठंड में मिलेगी राहत

आक के डोडों (फल) से निकलने वाला सफेद रेशा (फाइबर) बेहद हल्का, मजबूत और उच्च थर्मल इन्सुलेशन (गर्मी रोकने की क्षमता) से भरपूर होता है।विशेषज्ञों के अनुसार इस फाइबर की गुणवत्ता जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के प्रसिद्ध पश्मीना से भी बेहतर मानी गई है। इसके रेशों से तैयार जैकेट, दस्ताने, मोज़े, स्लीपिंग बैग और टेंट पारंपरिक ऊनी कपड़ों की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचे, कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए भारी-भरकम कपड़ों की जगह इन्हें पहनना और ले जाना बेहद आसान होगा।

यह एक अनूठी खोज

यह सफल प्रोजेक्ट भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ और अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉ. रूमा देवी के फाउंडेशन के बीच हुए एक साझा समझौते (MoU) का परिणाम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल पहल की सराहना की है।

बाड़मेर के छोटे से गांव से निकली, अब अंतरष्ट्रीय पहचान

डॉ. रूमा देवी का बाड़मेर के एक छोटे से गाँव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचना और अब भारतीय सेना के लिए थर्मल तकनीक विकसित करना महिला सशक्तीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' की एक बेमिसाल कहानी है। रूमा देवी ने थार रेगिस्तान की पारंपरिक कशीदाकारी (एम्ब्रॉयडरी) और एप्लिक वर्क को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में फैशन शो आयोजित कर राजस्थानी हस्तशिल्प को प्रमोट किया। वर्ष 2020 में उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 'भारत सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।पारंपरिक कला को जिंदा रखने और हजारों ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है। वह मशहूर टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी शामिल हो चुकी हैं।

---

28 साल पुराने कांकाणी केस में फिर गूंजी अदालत

13 जुलाई पर टिकी सलमान समेत सभी फिल्मी सितारों की सांसे, सलमान खान समेत अन्य कलाकारों ने मांगा अतिरिक्त समय

लोक टुडे। जोधपुर

जोधपुर के चर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार केस की फाइल जैसे ही सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में खुली, वैसे ही 28 साल पुरानी वो कहानी फिर सुर्खियों के तूफान में आ गई। जिसने बॉलीवुड, कानून और विश्नोई समाज को एक ही मंच पर ला खड़ा किया था। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे जैसे बड़े सितारों से जुड़ा यह हाईप्रोफाइल मामला अब फिर नई कानूनी करवट लेता दिखाई दे रहा है। अदालत में बचाव पक्ष ने तैयारी के लिए और वक्त मांगा तो वहीं इस केस से जुड़े लोगों की नजरें अदालत के हर शब्द पर टिकी रहीं। 1998 की उस रात का साया आज भी अदालत की दीवारों में गूंजता महसूस होता है। जब 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काला हिरण शिकार का मामला सामने आया था। वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई अब 13 जुलाई की तारीख पर आकर ठहर गई है, लेकिन इस तारीख ने फिर साबित कर दिया कि कांकाणी केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि देश की सबसे चर्चित कानूनी कहानियों में शामिल एक ऐसा अध्याय है, जिसका हर पन्ना आज भी लोगों की उत्सुकता और बहस को जिंदा रखे हुए है।

राजस्थान राज्यसभा चुनाव : राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनियां के नामों पर चर्चा तेज, रेस में सबसे आगे

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान की राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगा है। राजस्थान की तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने है, जिनमें दो सीटों पर बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय दिख रहा है। इसलिए बीजेपी इन दो सीटों पर जिन दो नामों पर चर्चा कर रही है, उनमें एक नाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और दूसरा नाम पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार के लिए इन दोनों नेताओं ने अथक प्रयास किये थे। राठौड़ और पूनिया के योगदान को बीजेपी नेता नकार भी नहीं सकते है। भाजपा कार्यालय में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राज्यसभा चुनावों को लेकर मंथन किया गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस दौड़ में शामिल है, लेकिन दो ही नेता राज्यसभा सदस्य बनाए जा सकते है। सूत्रों की माने तो सभी नेताओं ने इस पर विचार विमर्श के बाद राज्यसभा प्रत्याशी के चयन का काम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर छोड़ा गया.. सभी कोर कमेटी के सदस्यों ने निर्णय किया राज्यसभा सदस्यों के नाम सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। दोनों नेता विचार-विमर्श के बाद कुछ नाम दिल्ली भेज सकते है।

वैसे माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम दिल्ली दरबार को भेज सकते है...

अब आपको बताते है कि आखिर सतीश पूनिया का नाम क्यों भेजा जा रहा- सतीश पूनिया, छात्र जीवन से एबीवीपी से जुड़े रहे, राजस्थान विश्वविदयालय छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके है। संघ परिवार से शुरु से जुड़े रहे पार्टी में युवा मोर्चा और प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदों पर रह चुके है। वे पार्टी प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री , उपाध्यक्ष भी रह चुके है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गहलोत सरकार से पांच साल तक हर मोर्चे पर मुकाबला किया। विधानसभा चुनावों में संगठन को खड़ा किया और हर विधानसभा सीट तक प्रचार करने गए । लेकिन खुद की सीट पर ज्यादा फोकस नहीं करने के कारण वे चुनाव हार गए । चुनाव हारने पर पार्टी ने उन्हें हरियाणा जैसे प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा जहां सारी मीडिया रिपोर्टस और सर्वे कांग्रेस की सरकार की उम्मीद लगा रहे थे। ऐसे में सतीश पूनिया के सामने बड़ा चैलेंज था लेकिन उन्होंने जिस रणनीति से हरियाणा का चुनाव लड़ा वहां बीजेपी की बल्ले- बल्ले हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। सतीश पूनिया पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आंखों के तारे बन गए। लेकिन सतीश पूनिया रहे खाली हाथ... उनके समर्थकों का कहना है कि जाट समाज का बड़ा वोट बैंक सतीश पूनिया के कारण बीजेपी में गया लेकिन उन्हें क्या मिला । इसलिए अब कम से कम बीजेपी उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाकर उन्हें इसका इनाम दे। वैसे भी देखा जाए तो इससे पूर्व भी बीजेपी ने अधिकांश पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को राज्यसभा भेजा है। जिनमें रामदास अग्रवाल, ओम माथुर, ललित किशोर चतुर्वेदी, महेश शर्मा, मदन लाल सैनी, मदन राठौड़, तो अब सतीश पूनिया को भी कम से कम पूर्व अध्यक्ष के नाते ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। इसी तरह से राजस्थान में बीजेपी के कदावर नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह सात बार विधायक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे राजपूत समाज से आते है। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। राजेंद्र राठौड़ को पार्टी में कई पदों पर रहने का मौका मिला। वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम भैरोसिंह शेखावत सरकार में भी मंत्री रहे। मंत्री रहने के दौरान भी वे जनता से सीधे जुड़े रहे। विधानसभा चुनावों में कड़ी मेहनत की लेकिन खुद चुनाव हार गए। अभी हाल ही में बंगाल की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदू अधिकारी को चुनाव जीताने को लेकर चर्चा में आए। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यदि यहां के प्रभारी राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं होते वे भवानीपुर सीट कभी नहीं जीत सकते थे। इसलिए अब उनके समर्थकों का मानना है कि अब बीजेपी के पास वक्त है वो राजेंद्र सिंह राठौड़ को राज्यसभा भेजकर उन्हें सम्मान दे सके। राजेंद्र सिंह राठौड़ को राज्यसभा भेजने को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। सतीश पूनिया , राजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा भी कई नाम चर्चा में है । देखना ये है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम फैसला क्या रहता है।

यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब राजस्थान के लिए अटकलें हुई तेज

लोक टुडे। जयपुर

उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके साथ ही राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। बीजेपी विधायकों की उम्मीदें इसी ओर टिकी हुई है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में 24 मंत्री है, जबकि संवैधानिक तौर पर यहां 30 मंत्री हो सकते हैं। इसलिए करीब 6 विधायकों को मंत्री बनने का इंतजार है।

यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में 6 विधायकों को मंत्रियों की शपथ दिलाई गई।

केरलम फतह के बाद बढ़ा कद, क्या फिर राजस्थान के 'कैप्टन' बनेंगे सचिन पायलट

लोक टुडे। जयपुर

कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को फिर से राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। हाल ही में केरलम के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की वापसी में सचिन की बड़ी भूमिका रही है। सचिन पायलट को केरलम का सीनियर ऑबजर्वर बनाकर भेजा गया था, जहां दस साल बाद कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही सचिन पायलट की अहमियत भी बढ़ गई। माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पुरा हो चुका है और सचिन को बागडोर सौंपकर संगठन में जान फूंकी जा सकती है । पर खबर की हैडिंग

सचिन समर्थकों की बढ़ी उम्मीद :

केरलम में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। माना जा रहा है कि केरलम में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर सचिन पायलट ने चुनाव परिणाम को अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए सचिन पायलट समर्थकों को लगता है कि अब पार्टी आलाकमान उन्हें जल्द ही राजस्थान प्रदेश की कमान सौंप सकती है। राजस्थान के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पांच साल का कार्यकाल पुरा हो चुका है ऐसे में राजस्थान में नया अध्यक्ष बनाया जाना है। पायलट समर्थकों को लगता है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी जाए, जिससे वे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर सके। क्योंकि राजस्थान में ढ़ाई साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने है । इसलिए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि पायलट का संगठन चलाने का पुराना अनुभव है. संगठन पर पकड़ है। गांव- गांव ढाणी - ढ़ाणी कार्यकर्ताओं की फौज है जिससे वे आने वाले समय में बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। पायलट के कुछ समर्थकों ने पायलट को सीएम फेस घोषित करने की मांग तक डाली । उनका कहना है कि राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम फेस बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़े तो इसका फायदा जरूर पार्टी को मिलेगा। कई लोगों ने इस बार भी सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में कब क्या होने वाला है इसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। वहीं कई नेता सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी मांग कर रहे हैं। उनके समर्थकों को लगता है कि सचिन पायलट के साथ हमेशा अन्याय होता है।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

समय रहते चेतें

यह सामान्य बात नहीं कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। पिछले वर्ष खाद्य तेल आयात बिल करीब 20 अरब डालर का था। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि कृषि प्रधान देश होने और आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर बल देने के बाद भी देश में तिलहन फसलों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, जितना अपेक्षित है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके चलते उनके उत्पादन में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिली है, लेकिन इसी के साथ खाद्य तेल की मांग और खपत भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, उनके खानपान में तेलों की खपत बढ़ रही है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि जब संकट सामने आ खड़ा होता है, तब उससे बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाता है। खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का सघन अभियान तो बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था और उसकी लगातार समीक्षा भी की जानी चाहिए थी। बात केवल खाद्य तेलों की ही नहीं है, भारत को बड़ी मात्रा में दालों का भी आयात करना पड़ता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। कहना कठिन है कि दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए? जो भी हो, यह सही समय है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य आयातित वस्तुओं में कमी लाने के ठोस एवं दीर्घकालिक उपाय करे। यह सही है कि भारत में कच्चे तेल के अपेक्षित भंडार नहीं, इसलिए उसका आयात करना ही होगा, लेकिन आखिर हर तरह के ईवी वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए कोई आकर्षक प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं लाई जा पा रही है और उनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार द्रुत गति से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी तरह क्या कारण है कि किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है कि छोटे-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोल एवं डीजल की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?

> बात केवल खाद्य तेलों की ही नहीं है, भारत को बड़ी मात्रा में दालों का भी आयात करना पड़ता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। इस तथ्य पर हैरानी नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेलों के आयात में भी अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों के सेवन में कमी लाने की भी अपील की। उनका यह कहना सही है कि इससे सेहत सुधारने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता मिलेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत अपनी जरूरत भर का तिलहन क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है?

हिंसा की आग में फिर मणिपुर

मणिपुर तीन साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब ढाई सौ से ज्यादा लोग हिंसा में जान गंवा चुके हैं। हजारों लोगों के विस्थापन से राज्य का सामाजिक ताना-बाना टूट-सा गया है। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आखिर क्या वजह है कि उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग सका है। बीते बुधवार को उग्रवादियों ने एक बार फिर हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी। कांगपोकपी जिले में अंधाधुंध गोलीबारी में चार नागरिक भी घायल हो गए। इस घटना से नाराज नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को बंद कर दिया। गौरतलब है कि यह मार्ग मणिपुर को न केवल नगालैंड से, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ता है। इस समय राज्य में कानून-व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है, वह बेहद चिंताजनक है। एक बार फिर हुई हिंसा से साबित होता है कि सुरक्षा एजेंसियां सशस्त्र समूहों को नियंत्रित कर पाने में विफल रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का भी कोई असर नहीं दिखता। समझौते भी औपचारिक बनकर रह गए हैं। दरअसल, मणिपुर में शांति बहाली का कोई भी प्रयास इसलिए भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि परस्पर विरोधी समूहों को कायदे से अब तक संवाद की मेज पर नहीं लाया जा सका है और न ही शायद इसकी जरूरत महसूस की गई। यही वजह है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे सशस्त्र समूहों में एक-दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास खत्म नहीं हो रहा। यह निराशाजनक ही है कि जब भी राज्य में थोड़ी-बहुत स्थिति सुधरती दिखाई देती है, कोई न कोई उग्रवादी हमला राज्य को हिंसा की आग में झोंक देता है। सरकार अगर अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को संवाद के लिए राजी करती, तो शायद उनके बीच भरोसा कायम होता। मगर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के भीतर इस मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखती। आज राज्य में शांति प्रबंधन की नहीं, बल्कि उसे स्थापित करने के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिलकर काम करना होगा, अन्यथा मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के घातक नतीजे सामने आ सकते हैं।

> हाल ही में उग्रवादियों ने एक बार फिर हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी। कांगपोकपी जिले में अंधाधुंध गोलीबारी में चार नागरिक भी घायल हो गए।

शिक्षा का वैचारिक सपना और बिखरता भरोसा

सन् 2014 में सत्ता परिवर्तन केवल राजनीतिक घटना नहीं थी। यह उस लंबे वैचारिक संघर्ष का परिणाम भी माना गया जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दशकों से उठाते रहे थे। संघ परिवार लगातार यह आरोप लगाता रहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक और वामपंथी सोच का गहरा प्रभाव है। इतिहास लेखन से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक भारतीयता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी दृष्टि को कमजोर करने का विमर्श लगातार खड़ा किया गया। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सबसे अधिक उम्मीदें शिक्षा क्षेत्र से ही थीं। यह माना गया कि अब शिक्षा केवल डिग्री वितरण का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि भारत के वैचारिक पुनर्निर्माण का आधार बनेगी। अपेक्षा थी कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक संघर्ष के केंद्र से निकालकर शोध और नवाचार की प्रयोगशाला बनाया जाएगा। भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपरा को नया सम्मान मिलेगा। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शिक्षा मंत्रालय को ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो वैचारिक दृढ़ता के साथ बौद्धिक विश्वसनीयता भी रखता हो। अब 12 वर्षों के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सरकार शिक्षा क्षेत्र में वह संस्थागत और बौद्धिक नेतृत्व दे पाई जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र को वैचारिक पुनर्जागरण का केंद्र बनाया गया, वहीं सरकार कोई ऐसा सर्वमान्य बौद्धिक चेहरा खड़ा नहीं कर सकी जिसकी विद्वता को विरोधी भी स्वीकार करते। इससे पहले भाजपा या एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डॉ. मुरली मनोहर जोशी शिक्षा और संस्कृति विमर्श का मजबूत चेहरा थे। उनके समय में भी पाठ्यक्रमों और इतिहास लेखन को लेकर तीखे विवाद हुए, लेकिन उनकी बौद्धिक साख निर्विवाद थी। वे सार्वजनिक मंचों पर बहस करते थे। तर्क देते थे और आलोचनाओं का उत्तर वैचारिक भाषा में देते थे। असहमति के बावजूद उन्हें गंभीरता से लिया जाता था। सके उलट 2014 के बाद स्मृति ईरानी के कार्यकाल में रोहित वेमुला प्रकरण, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवाद और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आंदोलन जैसे मुद्दों ने विश्वविद्यालय परिसरों को अकादमिक बहस से ज्यादा राजनीतिक टकराव का केंद्र बना दिया। इसके बाद मंत्री बदलते रहे, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यापक बौद्धिक विमर्श विकसित नहीं हो पाया जो सरकार की वैचारिक परियोजना को गंभीर अकादमिक आधार देता। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई। बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास मातृभाषा पर बल और त्रिभाषा सूत्र जैसे कई प्रस्ताव लंबे समय बाद गंभीर सुधार की दिशा में दिखाई दिए। दक्षिण भारत में भाषा को लेकर अविश्वास बढ़ा और नीति का विमर्श फिर विवादों में उलझ गया। संवाद और सहमति निर्माण की जगह राजनीतिक ध्रुवीकरण अधिक दिखाई दिया।

माफिया के आगे कमजोर पड़ता तंत्र आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता बन चुका है...

सरकार और संघ परिवार अक्सर नालंदा और तक्षशिला के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार को वर्तमान के कार्यों से आंका जाता है। अतीतजीवी विमर्श से वर्तमान की चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता। सच यह है कि वैश्विक विश्वविद्यालयों की सूची में भारत अब भी निर्णायक उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। यह केवल सांख्यिकीय विफलता नहीं, बल्कि गहरे संस्थागत संकट का संकेत है। शोध, नवाचार और अकादमिक स्वायत्तता जैसे मानकों पर हमारे संस्थान अब भी संघर्ष कर रहे हैं। जिस समय भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना चाहिए था, उसी समय उसका शिक्षा तंत्र परीक्षा माफिया और कोचिंग उद्योग के जाल में उलझता चला गया। यहीं से सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दावा था कि अब प्रश्नपत्र लीक, भ्रष्टाचार और धांधली पर स्थायी रोक लगेगी। लेकिन विडंबना यह रही कि वही एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दी। 2015 के अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा विवाद के बाद सुरक्षित परीक्षा प्रणाली का जो सपना दिखाया गया था, वह 2024 के नीट विवाद और उसके बाद सामने आई गड़बड़ियों के बीच कमजोर पड़ गया। अब स्थिति यह है कि हर बड़ी परीक्षा के बाद छात्रों और अभिभावकों के मन में पहला प्रश्न यही उठता है कि प्रश्नपत्र लीक तो नहीं हुआ। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर संकट का संकेत है जिसे योग्यता आधारित मॉडल कहा गया था। राजस्थान से लेकर बिहार तक प्रश्नपत्र लीक गिरोहों के तार जिस तरह सामने आए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा माफिया अब एक संगठित समानांतर तंत्र बन चुका है। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि सरकार इस सिंडिकेट को तोड़ने में अब तक असफल क्यों रही। जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में छपाई श्रृंखला से लेकर हलकर्ता गिरोह, डिजिटल नेटवर्क और अंदरूनी मिलीभगत तक की बातें सामने आती रही हैं। इसके बावजूद कठोर और निर्णायक सुधार दिखाई नहीं देते। कोटा, पटना, दिल्ली और छोटे कस्बों में वर्षों मेहनत करने वाला छात्र अब यह महसूस करने लगा है कि उसकी लड़ाई किताबों से ज्यादा नेटवर्क से है। जब छात्र सड़कों पर थे और उनका भविष्य अनिश्चितता में था तब मंत्रालय का मौन सरकार की साख को और अधिक चोट पहुंचा गया। यही वह मोड़ था जहां मोदी सरकार की लंबे समय से बनी अभेद्य छवि पर सबसे गहरा आघात लगा। आर्थिक निर्णयों या राजनीतिक विवादों से अलग शिक्षा संकट ने सीधे उस मध्यवर्गीय और युवा वर्ग को प्रभावित किया जिसने इस सरकार को सबसे मजबूत समर्थन दिया था। आज का युवा शायद प्रश्न पूछ रहा है कि क्या व्यवस्था उसके साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर रही है। इतिहास की पुस्तकों के अध्याय बदलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन उस छात्र का भरोसा वापस लाना अत्यंत कठिन है जिसे लगने लगे कि इस देश में मेहनत से अधिक प्रभाव और प्रबंधन की शक्ति चलती है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा का विषय नहीं होती। यह किसी राष्ट्र की नैतिक विश्वसनीयता का आधार होती है। यदि छात्र को यह विश्वास ही न रहे कि उसकी मेहनत का निष्पक्ष मूल्यांकन होगा तो फिर कोई भी नई शिक्षा नीति या कोई भी वैचारिक विमर्श और कोई भी गौरवगान स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। यह तय है कि जब तक शिक्षा माफिया का सिंडिकेट नहीं टूटेगा और शिक्षा मंत्रालय को बौद्धिक गहराई तथा प्रशासनिक दृढ़ता वाला नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक नालंदा का गौरव केवल भाषणों का हिस्सा बना रहेगा। माफिया के आगे कमजोर पड़ता तंत्र आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता बन चुका है।

कमजोर पड़ती क्षेत्रीयता की राजनीति

विकास सारस्वत

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद असम और बंगाल में प्रचंड बहुमत वाली सरकारों ने कमान संभाल ली है तो पुडुचेरी में चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी विजय सरकार का आगाज हो चुका है। गत दिवस केरलम के मुख्यमंत्री का चयन भी हो गया। चुनाव परिणाम की बात करें तो असम, केरलम और पुडुचेरी में नतीजे आशा के अनुरूप ही रहे। असम में भाजपा के सामने कांग्रेस इस कदर साफ हुई, जैसे ब्रह्मपुत्र के सैलाब में नदी के बीच बालू से बने द्वीप बह जाते हैं। राज्य में कांग्रेस केवल निचले असम की मुस्लिम बहुल सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। जबकि उत्तर असम के असमिया बहुल जिलों में उसका सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया, जहां कभी पार्टी का अच्छा प्रभाव होता था। यह परिणाम पूरी तरह अपेक्षित भी था। राज्य में न केवल भाजपा सरकार द्वारा किया गया विकास साफ-साफ दिखाई देता है, बल्कि पार्टी असमिया अस्मिता और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति संवेदनशील भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की निजी लोकप्रियता भी पार्टी के लिए कारगर साबित रही। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की स्थिति पर चुनाव से पहले ही एक असमिया बुद्धिजीवी ने टिप्पणी की थी कि भंग नौकात निदिबा भोरी यानी टूटी नौका में आखिर कौन बैठता है?

केरलम के नतीजों में भी आश्चर्य सिर्फ इतना है कि यह परिवर्तन दस वर्ष बाद हुआ है, अन्यथा यहां हर पांच साल बाद मार्क्सवादी नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के बीच ही बारी-बारी से सत्ता बदलती रही है। यहां के नतीजों में महत्वपूर्ण बात यह रही कि यूडीएफ ने कोझीकोड, तिरुअनंतपुरम और कोल्लम जैसे वामपंथ के गढ़ भी ढहा दिए। मुस्लिम लीग के साथ हुए गठजोड़ ने कांग्रेस को विशेषकर उत्तरी केरलम में मदद पहुंचाई। इस गठबंधन से कांग्रेस को करीब छह प्रतिशत मतों का लाभ मिला। हालांकि यह परिणाम भी अनपेक्षित नहीं थे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को राज्य में 20 में से 18 सीटें मिली थीं। इसी तरह पुडुचेरी ने भी उसी परिपाटी का पालन किया है, जिसमें केंद्र पर निर्भरता होने के कारण केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव का झुकाव स्वाभाविक रूप से उस दल या गठबंधन की तरफ होता है, जिसकी केंद्र में सत्ता होती है। जो दो नतीजे सर्वाधिक चौंकाने वाले रहे, वे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आए। तमिलनाडु के नतीजे इस मायने में ऐतिहासिक हैं कि 50 वर्ष बाद द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूम रही सत्ता पर विराम लगा। सत्ताधारी द्रमुक को इन चुनावों में गहरा झटका लगा। बड़ा सवाल यही है कि इसे कितना व्यापक परिवर्तन माना जाए, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से तमिलनाडु की राजनीति में फिर से विजय के रूप में एक सिने स्टार का उदय हुआ। वहीं सर्वाधिक चर्चा में रहे राज्य बंगाल में सत्ता परिवर्तन के मायने शायद सबसे अधिक महत्व रखते हैं।

> कुल मिलाकर ये नतीजे दर्शाते हैं कि देश की राजनीति में क्षेत्रीयता की राजनीति कमजोर पड़ रही है और राष्ट्रवादी विचार का विस्तार हो रहा है।

बंगाल में लंबे समय बाद पूरी तरह हिंसा मुक्त चुनाव हुए। चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कड़े कदमों ने भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया। इसके चलते हुए रिकार्ड मतदान ने भय और भ्रष्टाचार के सहारे बनाई गई सत्ता को उखाड़ फेंका। स्पष्ट है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया। बंगाल के नतीजों में एक बड़ी बात यह भी रही कि आम बंगाली मतदाताओं ने कुछ बांग्ला बुद्धिजीवियों द्वारा संस्कृति और क्षेत्रीयता के नाम पर निर्मित श्रेष्ठता और विशिष्टता के भाव से ऊपर उठकर भारतीयता को महत्व दिया। निजी अनुभव से कहूं तो कभी सीबीआइ तो कभी ईडी और केंद्रीय बलों के ममता विरोध से खिन्न, परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध बंगाली मतदाताओं में एक प्रबल भाव था कि आखिर वे भी मूलतः हैं तो भारतीय ही। स्कूलों के उन्नयन के लिए लाई गई पीएमश्री और आयुष्मान जैसी योजनाओं का विरोध समझ से परे था। खस्ताहाल उद्योग और व्यापार, रोजगार की कमी और महिला सुरक्षा के अभाव ने बंगाली अस्मिता कार्ड नहीं चलने दिया। राजकीय सीमाओं से परे राज्यों के नतीजों के कुछ व्यापक निहितार्थ भी हैं। जैसे कि एक पहलू पार्टी पोषित भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा रहा। तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में एक ऐसी राजकीय व्यवस्था देखने को मिली, जहां पार्टी काडर को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ने के संस्थागत प्रयास हुए। बंगाल में नौकरियों के एवज में भ्रष्टाचार के अलावा निजी निर्माण से लेकर बिजली लाइन खिंचवाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कट मनी देनी पड़ती थी। सरकारी योजनाओं में भी यह व्यवस्था इतनी संस्थागत हो चली थी कि गरीब लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शुरू की गई समब्याथि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2,000 में से 200 स्थानीय कार्यकर्ताओं को देने की खबरें बहुत आम थीं। तमिलनाडु की बात करें तो मंत्रियों में एन. नेहरू, आइ. पेरियसामी और वीएस बालाजी पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए। दूसरा महत्वपूर्ण निहितार्थ यह कि हिंदू विरोध की राजनीति सिमटती जा रही है। जहां द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन और के. पोन्मुड़ी ने सनातन को मिटाने की बात कही, वहीं ममता बनर्जी ने काफिर जैसे इस्लामपरस्त शब्दों द्वारा मुस्लिम वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। ममता की जय श्रीराम के आह्वान से खीझ कैमरों के सामने भी स्पष्ट दिखी। जनता ने मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध की राजनीति को सिरे से नकारा है। तीसरा निहितार्थ सीमावर्ती राज्यों असम और बंगाल में घुसपैठ से जुड़ा है। चौथा, देश में सर्वाधिक क्षेत्रीयता का भाव लिए हुए तमिलनाडु और बंगाल में मतदाताओं ने भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को नकारा है। कुल मिलाकर ये नतीजे दर्शाते हैं कि देश की राजनीति में क्षेत्रीयता की राजनीति कमजोर पड़ रही है और राष्ट्रवादी विचार का विस्तार हो रहा है।

फिजूलखर्ची की संस्कृति

अच्छा हो कि सामान्य दिनों में भी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने एवं विदेशी मुद्रा बचाने की संस्कृति विकसित की जाए।

यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वे जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं, उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। उनकी ओर से अपनी कारों के काफिले को छोटा किए जाने के बाद कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया है। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे, लेकिन ऐसा ही गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी दिखना चाहिए। इसी के साथ ही सांसदों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ नौकरशाहों को भी ऐसा ही करना चाहिए। किफायत का परिचय देना किसी सरकार या दल विशेष का विषय नहीं। यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और केवल वर्तमान की ही नहीं। चूंकि हम एक विकासशील देश हैं, इसलिए मितव्ययिता का परिचय तो सदैव ही दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक नेताओं और नौकरशाहों की ओर से दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बीच किफायत की जगह फिजूलखर्ची की संस्कृति ने जड़ें जमा ली हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि जो जितने लंबे काफिले से चलता है, वह उतना ही धमक-हनक वाला माना जाता है। दिखावे वाली इस मानसिकता से मुक्ति पाने की सख्त जरूरत है। आज यदि ऊर्जा संकट के चलते मंत्रीगण दो-तीन कारों के साथ चलने को उपयुक्त समझने लगे हैं, तो इसके पहले वे इसकी जरूरत क्यों नहीं समझ रहे थे? आखिर ऐसा तो है नहीं कि ऊर्जा संकट के पहले पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन देश में ही हो रहा था या फिर उनका आयात बहुत सस्ता था। सरकारी तंत्र को तो इससे कहीं अच्छे से अवगत होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक खपत पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ही होती है। सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी लाने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने वाले अन्य दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान देना होगा। विदेशी मुद्रा की एक बड़ी खपत पर्यटन के लिए विदेश यात्राओं के चलते होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि देश में वैसे पर्यटन स्थल और पर्यटकों के अनुकूल माहौल विकसित नहीं हो पाया है, जैसा मालदीव, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों ने विकसित कर लिया है। यह तब है, जब भारत पर्यटन स्थलों की दृष्टि से कहीं अधिक समृद्ध है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि अब लोग शादियां, पार्टियां आदि करने के लिए भी विदेश जाने लगे हैं। विदेशी मुद्रा की एक बड़ी खपत विदेश पढ़ने वाले जाने वाले छात्रों के कारण भी होती है। हमारे छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने इसलिए जाते हैं, क्योंकि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा हो कि सामान्य दिनों में भी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने एवं विदेशी मुद्रा बचाने की संस्कृति विकसित की जाए।

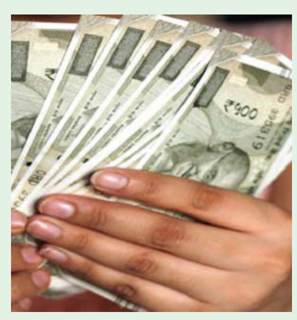

आखिर हर साल क्यों बेबस दिखते हैं लोग? आंधी-तूफान और बिजली ने मचाई तबाही

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने से लेकर सटीक पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी स्तर पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार की शाम को तेज आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि एक तरह से कहर बरपा रही थी और आम लोग उसके सामने लाचार थे।

कई जगहों पर तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। कितनी ही जगहों पर भारी पेड़ उखड़कर वाहनों पर गिर गए और सड़कों के किनारे लगे बोर्ड उड़कर तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे। करीब चौबीस घंटों के दौरान करीब सौ लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई जिलों में दो हजार से ज्यादा गांवों में बिजली गुल हो गई। कुदरत के इस कहर के बाद मौसम विभाग ने राज्य के अड़तीस जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर पीली चेतावनी जारी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूर्वानुमानों के बावजूद कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिनमें तूफान या बिजली गिरने की घटनाएं आम लोगों पर कहर बनकर टूटती हैं। ।हिर है, मौसम की अपनी गति होती है और प्रकृति में उथल-पुथल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष अचानक मौसम का रुख बिगड़ने की आशंका के बावजूद आम लोग इससे बचाव के लिए एहतियात नहीं बरत पाते। इसका खमियाजा यह सामने आता है कि जिन हालात में कुछ लोगों की जान बच सकती थी, उसमें नाहक ही कई लोगों की जान चली जाती है। राज्य में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती ढांचे और दक्षिण राजस्थान से आ रही हवाओं के प्रभाव से वहां कई जगहों पर अस्सी से सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर न केवल घरों की छत उड़ गई, बल्कि लोगों के लिए पांव टिकाना भी मुश्किल था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मौसम में बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण के अभाव का नुकसान आम लोगों को किस स्तर पर उठाना पड़ता है। संभव है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ-साथ मौसम साफ होने लगे और उसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि साल के इन महीनों में कई बार तेज रफ्तार से चलने वाला तूफान और ओलावृष्टि कई स्तर पर आम लोगों के लिए व्यापक क्षति और खतरे का वाहक बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा, इस बात का अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि हाल के वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में तेज इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि अकेले इस कारण से भी देश भर में काफी संख्या में लोगों की जान जा रही है। मौसम में तेज उतार-चढ़ाव को रोकना भले ही संभव न हो, लेकिन उससे बचाव के कुछ मामूली उपाय करके जानमाल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।

> पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है।

ग्लोबल कंपनियों का नया ठिकाना बना अलवर, जापानी जोन बनने पर मिलेंगे हजारों रोजगार के अवसर

लोक टुडे। अलवर

राजस्थान के अलवर जिले के घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में बनने जा रहा यह नया जापानी ज़ोन राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जापानी हब होगा। अलवर में ही स्थित 'नीमराणा' देश का पहला सफल जापानी ज़ोन है, जहाँ डायकिन और निसिन जैसी बड़ी जापानी कंपनियाँ काम कर रही हैं। नीमराणा में ज़मीन की कमी होने के कारण अब रीको द्वारा घिलौट में 964 बीघा ज़मीन पर यह दूसरा ज़ोन विकसित किया जा रहा है। घिलौट की भौगोलिक स्थिति दिल्ली-एनसीआर के नजदीक है, जिससे कंपनियों को देश के बड़े बाज़ारों तक माल पहुँचाने में बहुत आसानी होगी।

भारी निवेश और रोज़गार के अवसर :

इस नए ज़ोन में जापानी कंपनियों द्वारा 5 हजार करोड़ से अधिक का भारी निवेश किए जाने की उम्मीद है। इस ज़ोन के पूरी तरह शुरू होने से राजस्थान और आस-पास के क्षेत्रों के हज़ारों कुशल और अकुशल युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।

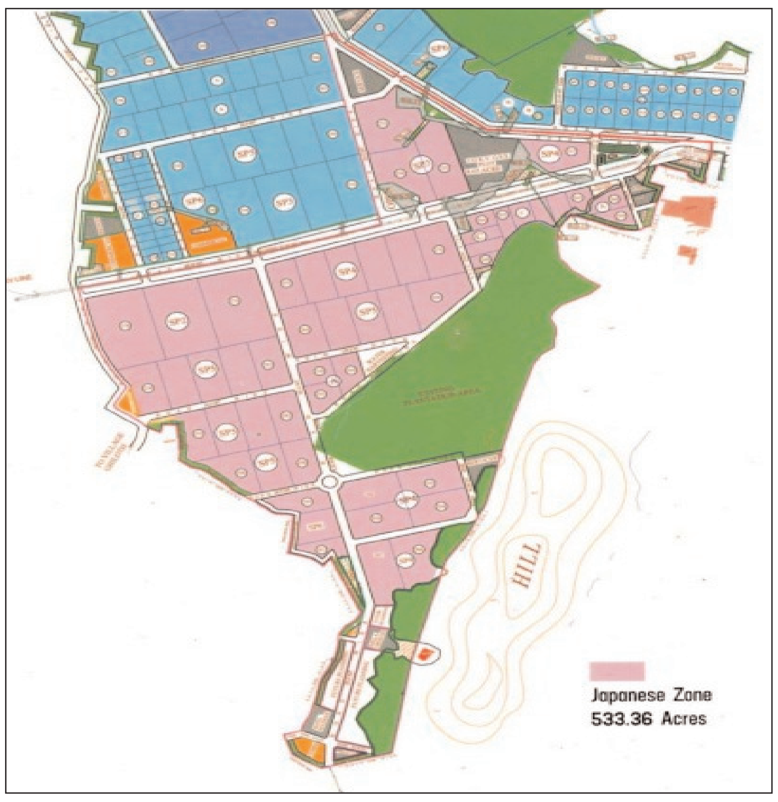

इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस :

यहाँ मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और आधुनिक इंजीनियरिंग से जुड़ी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। घिलौट में पहले से ही एक सिरामिक और ग्लास ज़ोन मौजूद है, जिससे इस नए जापानी ज़ोन को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा।

प्रमुख शासन सचिव ने जोधपुर में एमडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मरीजों को गर्मी में राहत देने के लिए व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सोमवार को मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर का औचक निरीक्षण कर विभिन्न चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार व्यवस्था, ट्रॉमा सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रीमती राठौड़ ने ट्रॉमा सेंटर, सीटी स्कैन एवं एक्स-रे विंग, ओपीडी सेक्शन, आपातकालीन विभाग, आईसीयू-डी रेड जोन, ट्रॉमा कैजुअल्टी वार्ड तथा मल्टी लेवल आईसीयू वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न इकाइयों में व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उपचाराधीन मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

मरीजों को गर्मी में राहत देने के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान श्रीमती राठौड़ ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों एवं उनके साथ आने वाले परिजनों को अधिकतम राहत उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने अस्पताल परिसर में कूलिंग सिस्टम, छायादार टेंट, पेयजल एवं बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

न्यूज इन बॉक्स

'जयपुर पुलिस' फिल्म का प्रीमियर शो रहा हाउसफुल

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और पूर्व एसीपी भी पहुंचे

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थानी सिनेमा की फिल्म 'जयपुर पुलिस' का प्रीमियर शो जयपुर के प्रतिष्ठित राजमंदिर सिनेमा में आयोजित किया गया। प्रीमियर शो पूरी तरह हाउसफुल रहा और बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना दी। फिल्म की दमदार कहानी, रोमांचक घटनाक्रम, भावनात्मक प्रस्तुतिकरण और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े पहलुओं ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। सामाजिक संदेश और मनोरंजन का संतुलित मेल फिल्म को दर्शकों के लिए खास बनाता है। फिल्म में पुलिस व्यवस्था, समाज और मानवीय भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। प्रीमियर शो के दौरान फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। कलाकारों में हर्षित माथुर, दीपेंद्र सिंह, योगिता, अल्ताफ, वीर, अजय सक्सेना, संगीता सिंह, अभिषेक, ज्योत्सना, संतोष कंवर, त्रिलोक जी, मानस आलोक और सेलिना पिया शामिल रहे।

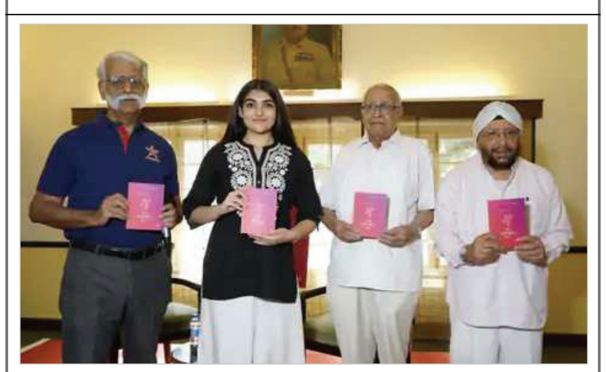

जयपुर की 14 वर्षीय लेखिका कियारा ग्वाला की बुक द ओपनिंग एक्ट हुई लॉन्च

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर की 14 साल की लेखिका कियारा ग्वाला के कविता संग्रह द ओपनिंग एक्ट को अशोक क्लब में लॉन्च किया गया। इस दौरान उन्होंने जयपुर के लेखक और पब्लिसिस्ट जगदीप सिंह के साथ संवाद किया। इससे पूर्व, पुस्तक का औपचारिक विमोचन पूर्व पुलिस महानिदेशक, एस.एन. जयरथ, लेखिका कियारा ग्वाला, जगदीप सिंह और अजय सिंघा की ओर से किया गया। चर्चा के दौरान कियारा ने बताया कि यह पुस्तक उनके स्वर्गीय दादा को समर्पित हैं, विशेषकर कविता द मैन हू टॉट मी एवरीथिंग और मैंगो सीजन। इस दौरान कियारा ने पुस्तक से कुछ कविताओं का पाठ किया, जिसने श्रोताओं को भावुक कर दिया। अपनी कविताओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन भावनाओं को अभिव्यक्ति देना चाहती हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। इसमें स्पष्ट जवाब ढूंढने के बजाय, अनिश्चितता को अपनाया है।

उप मुख्यमंत्री ने किया केसरपुरा ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण

केसरपुरा पंचायत भवन बनेगा राजस्थान के लिए मॉडलः उपमुख्यमंत्री, दिया कुमारी

जयपुर(नि.सं.)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के केसरपुरा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण करने के साथ ही ग्राम विकास चौपाल में आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अरावली एक्सप्रेस ट्रेन से जयपुर से अजमेर पहुंची। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने के लिए रेल मार्ग को चुना। अजमेर के केसरपुरा में उप मुख्यमंत्री द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह तथा ग्राम विकास चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केसरपुरा का ग्राम पंचायत भवन पूरे राजस्थान के लिए मॉडल है। इस प्रकार के भवन सभी ग्राम पंचायतों को बनाने चाहिए। सुविधायुक्त भवन से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे है। इनका प्रभाव नजर आने लगा है। स्थानीय जन प्रतिनिधि भी क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते है। प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अजमेर के विकास में योगदान देना गर्व का विषय है। सरकार ने ग्राम विकास रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई है। साथ ही ग्राम विकास चौपाली से आमजन की समस्याओं के समाधान भी हुए है। सुझाव पेटिका में प्राप्त सुझावों पर भी अमल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गांव तक बार-बार आ रही है। जनता की सेवा करने के लिए सरकार चुनी गई है।

मिस राजस्थान

मिस राजस्थान बनने का सपना लेकर जयपुर पहुंची युवतियां

गांवों से आई लड़कियां बोलीं- अब बेटियां केवल घरेलू दायरों तक सीमित नहीं

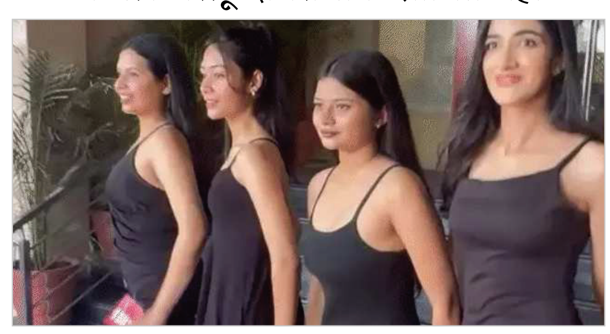

जयपुर(नि.सं.)। प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान 2026 के आखिरी ऑडिशन में प्रदेशभर की गर्ल्स नज़र आईं। फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में इस साल 6500 से अधिक गर्ल्स के रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि जयपुर में आयोजित अंतिम ऑडिशन में करीब 1300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपने टैलेंट और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले हुए पहले ऑडिशन में भी करीब 1200 गर्ल्स ने भाग लिया था। 200 फीट स्थित एक होटल में आयोजित इस ऑडिशन के दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह, ग्लैमर और सपनों से भरा नज़र आया। राजस्थान के छोटे-छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आई प्रतिभागियों ने मंच पर कैटवॉक, इंट्रोडक्शन और सवाल-जवाब राउंड के ज़रिए अपनी प्रतिभा को जजेज के सामने प्रस्तुत किया।

सीकर में 4000-बीघा जमीन को लेकर किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव

कहा- एक इंच जमीन भी नहीं बचेगी; प्रस्तावित रेलवे लाइन-एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध, ये हैं 4 मांगें

सीकर(वि.सं.)। सीकर जिले के तारपुरा और दादिया क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू कर दिया है। प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवलगढ़-बेरी-बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी-दादिया अंडरपास के विरोध में हजारों किसान सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में करीब आधे घंटे तक नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद एडीएम डॉ. रतन कुमार स्वामी को ज्ञापन दिया गया। सीकर जिले के दादिया और तारपुरा गांव के किसानों ने विशाल महापंचायत का आयोजन कर सरकार की अधिग्रहण नीति पर कड़ा ऐतराज जताया था।

डाइंग-प्रिंटिंग कार्यशाला का सफल आयोजन

कानोड़िया महाविद्यालय में तीन दिवसीय टेक्सटाइल डाइंग-प्रिंटिंग कार्यशाला का सफल आयोजन

जयपुर(नि.सं.)। कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान एवं GPEM विभाग द्वारा 14 से 16 मई 2026 तक तीन दिवसीय टेक्सटाइल डाइंग एवं प्रिंटिंग कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को पारंपरिक और आधुनिक वस्त्र रंगाई एवं छपाई तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना रहा। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने छात्राओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनके रचनात्मक और व्यावहारिक कौशल को नई दिशा देती हैं। पहले दिन सत्र विशेषज्ञ पापिया बनर्जी (सहायक आचार्य, GPEM विभाग) ने टेक्सटाइल डाइंग और प्रिंटिंग की मूलभूत जानकारी दी। उन्होंने फैशन और होम फर्निशिंग में इन तकनीकों के महत्व को विस्तार से समझाया।

दूसरे दिन श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय की सहायक आचार्य निक्कू शेखावत ने लहरिया, प्लीटिंग, बांधनी, शिबोरी और मार्बलिंग जैसी टाई-एंड-डाई तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया। साथ ही डाई बाथ तैयार करने की प्रक्रिया भी सिखाई। तीसरे दिन छात्राओं ने ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग का व्यावहारिक अभ्यास किया। इस दौरान प्रिंटिंग टेबल की सही व्यवस्था, रंगों की तैयारी और आकर्षक प्रिंट बनाने के गुर साझा किए गए।

टोंक में हुनर का जलवा

मिस एंड मिसेज बनास 2026 के दूसरे ऑडिशन में बिखरा प्रतिभाओं का जलवा

टोंक(वि.सं.)। छोटे शहरों और कस्बों की छिपी हुई प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से नटराज स्टूडियोज़ द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेज बनास 2026 के दूसरे ऑडिशन राउंड का भव्य आयोजन आज द ओशियन रिज़ॉर्ट, टोंक में किया गया। इस ऐतिहासिक सौंदर्य और प्रतिभा प्रतियोगिता में टोंक सहित आसपास के कई क्षेत्रों से आई संस्कारी व आधुनिक युवतियों और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने रैंप वॉक, परिचय और टैलेंट राउंड में अपने अद्भुत आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन कर जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टोंक के इतिहास में पहली बार इस स्तर के बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना -2026

प्रदेश में 56 हजार वरिष्ठजन करेंगे तीर्थ दर्शन, देवस्थान विभाग शीघ्र निःशुल्क तीर्थ यात्रा के प्राप्त करेगा आवेदन

जयपुर (नि.सं.)। प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग की महत्वपूर्ण वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना - 2026 के तहत 50 हजार को रेल एवं 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। देवस्थान विभाग आयुक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के अनुसार उक्त यात्रा के संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र नवीन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट http://devasthan.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देवस्थान आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की बजट घोषणा के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना - 2026 के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को देश में सुप्रसिद्ध 15 जन आस्था के तीर्थ स्थलों पर रेल व हवाई मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि हवाई मार्ग द्वारा तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है।

लॉटरी से चयनः अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान गितेश श्री मालवीया ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक आवेदन स्वयं एवं ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं।

अवैध शराब | आबकारी आयुक्त के निर्देशन में कार्रवाई

अवैध मदिरा के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति कोटा में 60 लाख की अवैध शराब ट्रक से बरामद

जयपुर(नि.सं.)। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेश में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत एक्शन मोड में अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत कोटा में नाकाबंदी कर एक ट्रक की तलाशी लेने पर 60 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हनुमानगढ़, उदयपुर एवं जोधपुर में भी ट्रकों से अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से प्रदेश में अन्य राज्यों की शराब तस्करी पर

रोक लगाने एवं राजस्व क्षति को रोकने में सहायता मिलेगी।

1360 कार्टन में 65280 पव्वे बरामद

अतिरिक्त आयुक्त कोटा जोन नरेश कुमार मालव ने बताया कि आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में अवैध शराब के विरूद्ध गश्त, नाकाबंदी एवं दबिश की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर कोटा में रविवार रात्रि नेशनल हाईवे 52 नया टोल प्लाजा गोपालपुरा के समीप नाकाबंदी के तहत ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर टाट की बोरियों के नीचे कार्टन में छुपाकर रखी गई फोर सेल इन चंडीगढ़ शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। मौके पर ब्रांड राजस्थानी व्हीस्की के 1360 कार्टन में 65 हजार 280 पव्वे बरामद हुए। उक्त शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख रूपए आंकी गई है। उक्त कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी बारां देवेन्द्र गिरी, जिला आबकारी अधिकारी कोटा विवेक शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी, नारायण सिंह तोमर के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी निरीक्षक चेतन, प्रदीप मीणा, पीओ प्रमोद सिंह, हंसराज मीणा, पृथ्वीराज सिंह मीणा मय जाप्ता शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कैंप जनसेवा केंद्र में होंगे तब्दील

आदिवासियों को नौकरी में मिलेगा 15 फीसदी आरक्षणः अमित शाह

बस्तर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'शहीद वीर गुण्डाधुर सेवा डेरा' जन सुविधा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलमुक्त भारत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में जहां-जहां सुरक्षा कैंप बनाकर सिक्योरिटी वैक्यूम समाप्त किए थे, अब वहां कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आज का

दिन सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महज छह महीनों के भीतर, यह केंद्र जो अभी केवल एक सरकारी पहल जैसा दिखता है, स्थानीय आदिवासियों की मौजूदगी और उनकी हंसी-खुशी से गुलजार, जीवन से भरपूर नजर आएगा। जिस जमीन पर मैं आज खड़ा हूं, वह अपने आप में भारत के हर नागरिक के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है। यह शहीद वीर गुंडा धुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आज, उनसे प्रेरणा लेते हुए नेतानार कैंप (जो 2013 से एक सुरक्षा चौकी के रूप में काम कर रहा था) अब आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित एक सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आजादी देशभर में बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद ही आजादी का सूर्य उदय हुआ है। इस दौरान बस्तर का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम बहुत जल्द करेंगे।

राज्यपाल बागडे ने राजस्थान विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया

नव निर्मित प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति का द्योतकःराज्यपाल

जयपुर(नि.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नव निर्मित प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। उन्होंने इस दौरान विधानसभा के विभिन्न 13 द्वारों का भी नामकरण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का गौरवमय इतिहास रहा है। स्वतंत्र भारत में भले ही 1952 में विधानसभा गठित हुई परन्तु राजस्थान में 1913 में स्वतंत्रता से पूर्व ही महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर विधानसभा की शुरुआत कर दी थी। इस इतिहास में अमृतकाल के अवसर पर प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी की पहल पर तैयार लोगो राजस्थान के जन मानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने प्रतीक चिन्ह में

सम्मिलित राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी और विधानभवन की छवियों की चर्चा करते हुए कहा कि यह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सवधर्मिता से जीवन जीने वाले लोगों की जीवटता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है। उन्होंने खेजड़ली में पेड़ों के लिए हुए बलिदान की वृक्ष संस्कृति की चर्चा

करते हुए कहा कि इसके साथ रोहिड़े पुष्प का समावेश समन्वय की संस्कृति का द्योतक है। राज्यपाल ने भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की चर्चा करते हुए कहा कि एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला प्रतिनिधिमंडल

कोटा डोरिया को मिलेगी नई पहचान, पूर्वोत्तर के एरी सिल्क से होगा संगम

प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान के पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी सिल्क को मिलाकर नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। रविवार को कोटा स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के सचिव संजय जाजू और फैशन डिजाइनरों व बुनकरों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला ने कहा कि कोटा डोरिया केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि हाड़ौती की पहचान और यहां के बुनकरों की मेहनत का प्रतीक है। इसे पूर्वोत्तर के एरी सिल्क के साथ जोड़कर नया फैब्रिक तैयार करने से देश की दो समृद्ध हस्तकरघा परंपराओं को नई पहचान मिलेगी और कारीगरों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के '5F Vision' - Farm to Fibre, Fibre to Fabric, Fabric to Fashion, Fashion to Foreign - को आगे बढ़ाने वाली है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस पहल से राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनकरों एवं कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे और भारतीय हस्तकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। कोटा के फैशन डिजाइनरों ने भी प्रस्तावित टेक्सटाइल फ्यूजन को लेकर अपने सुझाव साझा किए।

न्यूज ब्रीफ

मंदिर-श्मशान के बाहर खड़े वाहनों को चुराने वाले बदमाश गिरफ्तार

नंबर प्लेट हटाकर इंजन-चेसिस नंबर मिटाते थे; चोरी की 3 स्कूटी बरामद

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने चोरी की तीन स्कूटी बरामद की गई है। दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों धार्मिक स्थलों, मंदिरों और श्मशान के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। पूछताछ में चोरी की गई वारदात करना कबूला है। डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार सोनी और रवि शर्मा है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में कई वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। डीसीपी ने बताया कि शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

तेज रफ्तार कार पलटने से होटल मालिक की मौत

साथियों ने खिड़की से बाहर कूदकर जान बचाई, बेकरी के सामने पलटी गाड़ी

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर में रविवार रात बेकाबू कार के पलटने से होटल मालिक की मौत हो गई। कार में मौजूद अन्य युवकों ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। करणी विहार थाने के स्ठ्ठ ओम प्रकाश ने बताया- हादसे में सुरेंद्र सिंह शेखावत (26) निवासी पलसाना सीकर की मौत हुई है। वह सिरसी रोड पर सैफरॉन होटल चलाते थे। रविवार रात 12 बजे होटल से वे दोस्तों के साथ दो गाड़ियों में 200 फीट बाइपास की तरफ जा रहे थे। 100 से अधिक स्पीड होने के कारण डिवाइडर बचाने की कोशिश में कार सिरसी रोड पर जयपुर बेकरी के सामने पलट गई।

कार में दोस्त मौजूद थे

कार में उनके साथ पांच दोस्त भी मौजूद थे। हादसे के वक्त सुरेंद्र ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे थे।

एसएमएस हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में: कंपनी गार्डों के रहते 20 लाख का सामान हो चुका चोरी

फर्म को फिर जिम्मा देने की तैयारी

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में जिस कंपनी के पास हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके रहते हॉस्पिटल से पिछले डेढ़ साल में 20 लाख रुपए के सामान चोरी हो गए। वहीं कंपनी न तो हॉस्पिटल में निर्धारित संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा पा रही और न ही ट्रेंड (प्रशिक्षित) गार्ड। इसे देखते हुए हॉस्पिटल प्रशासन को मजबूरी में नए सिरे से सुरक्षा गार्ड आपूर्ति के लिए टेंडर करने पड़ रहे हैं। इन नए टेंडर में भी अब वापस इसी कंपनी

को सुरक्षा का जिम्मा देने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में स्ब्ब हॉस्पिटल (मैन बिल्डिंग, ट्रोमा सेंटर, चरक भवन, धन्वंतरि ब्लॉक) में सुरक्षा गार्ड आपूर्ति का टेंडर मैसर्स बिमला एंटरप्राइजेज नई दिल्ली की फर्म के पास है। कंपनी को जनवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक दो साल का टेंडर दिया गया। इसके तहत कंपनी को रोज 550 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने हैं। कंपनी पहले दिन से आज तक पूरी संख्या में गार्ड उपलब्ध नहीं करवा पा रही। इसे देखते हुए एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन ने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाए वापस नए सिरे से गार्ड आपूर्ति के टेंडर कर दिए। इस बार टेंडर एक साथ न करके अलग-अलग बिल्डिंग में अलग-अलग कंपनियों से सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि इस बार भी इस टेंडर में मौजूदा कंपनी को ही सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति का टेंडर देने की तैयारी चल रही है। जबकि ऐसी स्थिति में कंपनी पर न केवल भारी पेनल्टी लगानी चाहिए।

सुवेंदु कैबिनेट का बड़ा फैसला

सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अन्नपूर्णा भंडार योजना भी लागू

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की कैबनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू करना राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल थी। उन्होंने कहा कि पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं के नाम स्वतः ही नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ दिए जाएंगे और राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया है।

अप्रेल 2026 में 11 हजार 235 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति

बकाया वसूली में लाएं तेजी, राजस्व प्रकरणों का हो शीघ्र निस्तारणःशर्मा

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व अर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने तथा नवाचार एवं तकनीक अपनाने के लिए भी निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों को कर चोरी करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कार्ययोजना बनाकर राजस्व से संबंधित केसों के पूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य सचिव को राजस्व प्राप्ति प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करे। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग को ऑडिट केसों की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, बेहतर एवं प्रभावी स्क्रूटिनी के नए पैरामीटर्स विकसित करने के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खान विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खनन से जुड़ी गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी खानों को नीलाम किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट बोला- उमर खालिद को बेल मिल सकती थी

दिल्ली दंगा मामले के अपने फैसले पर आपत्ति जताई, कहा- जमानत अधिकार है, जेल अपवाद

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सोमवार को यह बयान सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को-टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने केए नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 319 शिक्षकों और 17 महिला पर्यवेक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र

रांची (एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक राजकीय समारोह में 319 इंटर व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों (शिक्षकों) और 17 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले चार महीनों के भीतर अकेले शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है और आगामी दो से चार महीनों के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों और नए पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि सरकारी नौकरी केवल वेतन पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राज्य के विकास में योगदान देने की जिम्मेदारी भी है।

जयपुर में पहली बार प्रदर्शित हुआ दुर्लभ रत्नः100 किलो का अमेथिस्ट एगेट, जिसमें दिखते हैं ब्रह्मा-विष्णु-महेश

जयपुर(नि.सं.)। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार दुर्लभ रत्न प्रदर्शित किया गया है। जिसकी आकृति कैलाश पर्वत के जैसी है और जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृति दिखाई देती है। इस विशेष रत्न को ब्राजील से लाया गया है, जिसका वजन 100 किलो है। इस दर्लभ रत्न को खजाना महल जेम एंड ज्वेलरी म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम प्रशासन के अनुसार यह एक सिंगल पीस अमेथिस्ट एगेट है, जो प्राकृतिक रूप से तीन जुड़े हुए हिस्सों में विकसित हुआ है। इसकी संरचना कैलाश पर्वत जैसी प्रतीत होती है और भीतर मौजूद क्रिस्टल संरचनाएं त्रिदेव के स्वरूप का एहसास कराती हैं। यही कारण

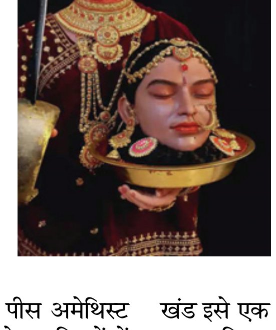

है कि इसे भूगर्भीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है।

प्रकृति की अद्भुत कलाकारी

इस अमेथिस्ट एगेट की खासियत केवल इसका आकार या वजन नहीं, बल्कि इसकी आंतरिक संरचना भी है। पत्थर के भीतर प्राकृतिक रूप से कैल्साइट का एक टुकड़ा समाहित है, जो इसकी सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व को और बढ़ाता है। तीन गोलाकार जुड़े हुए अमेथिस्ट खंड इसे एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं।

म्यूजियम निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि यह पत्थर केवल एक भूगर्भीय नमूना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक कला का अद्भुत संगम है।

औचक निरीक्षण अभियान | **पेट्रोल/डीजल की मात्रा की जांच हेतु प्रदेशभर में औचक निरीक्षण अभियान**

43 पेट्रोल पम्पों के नोजल किए सीज/बंद

जयपुर(नि.सं.)। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई में प्रदेशभर के कई पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। विभाग द्वारा 7 जिलों में की गई सघन जांच के दौरान 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 गड़बड़ नोज़ल जब्त/बंद किए गए। जांच में सामने आया कि कई पेट्रोल पंप हर 5 लीटर पर 30 से 60 एमएल तक कम ईंधन दे रहे थे। बड़ी मात्रा में बिक्री होने के कारण यह कमी हर महीने उपभोक्ताओं को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रही थी। सिरोही जिले में 7 पेट्रोल पंपों के 9 नोज़ल बंद किए गए। रामपीर फिलिंग स्टेशन, पवन

फिलिंग, करणी फ्यूल, देवनगरी पेट्रोलियम सर्विस, पार्वती दरिया फिलिंग स्टेशन, सुरेन्द्र जितेन्द्र ट्रेडर्स एवं भगवती फिलिंग स्टेशन पर 40 से 50 एमएल तक शॉर्ट डिलीवरी मिली। यहां प्रतिमाह 90 से 360 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था, जिससे करीब रु.1.14 लाख की अनुमानित हानि हो रही थी। अलवर जिले में सिंघल सर्विस स्टेशन और चौधरी सर्विस स्टेशन के 5 नोज़ल बंद किए गए। सिंघल सर्विस स्टेशन पर 30 से 60 एमएल तक कम डिलीवरी मिली, जहां प्रतिमाह 648 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था। जिले में कुल अनुमानित हानि रु.91 हजार से अधिक आंकी गई। नागौर जिले में 4 पेट्रोल पंपों के 11 नोज़ल जब्त किए गए। नंदलाल राजेश कुमार कछवाहा फिलिंग स्टेशन, गुलाबदास आत्माराम, मारवाड़ फिलिंग स्टेशन एवं आर एल सिहाग पेट्रोलियम पर प्रतिमाह 54 से 378 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था। यहां करीब रु.97 हजार की आर्थिक हानि सामने आई। भीलवाड़ा जिले में 3 पेट्रोल पंपों के 4 नोज़ल बंद किए गए। दीपक पेट्रोलियम, शिव इंडियन ऑयल एवं श्री श्याम फिलिंग स्टेशन पर प्रतिमाह 34 से 90 लीटर तक कम पेट्रोल दिया जा रहा था। सीकर जिले के सीएसआरबी फिलिंग स्टेशन नायरा के 4 नोज़ल बंद किए गए, जहां प्रतिमाह 216 लीटर तक शॉर्ट डिलीवरी सामने आई।

पाली जिले में मा आई जी फिलिंग, पूजा एचपी पेट्रोलियम, पार्श्व एनर्जी एवं कछ्वा बस सर्विसेज के 5 नोज़ल बंद किए गए। यहां प्रतिमाह 45 से 180 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था।

[illegible]